


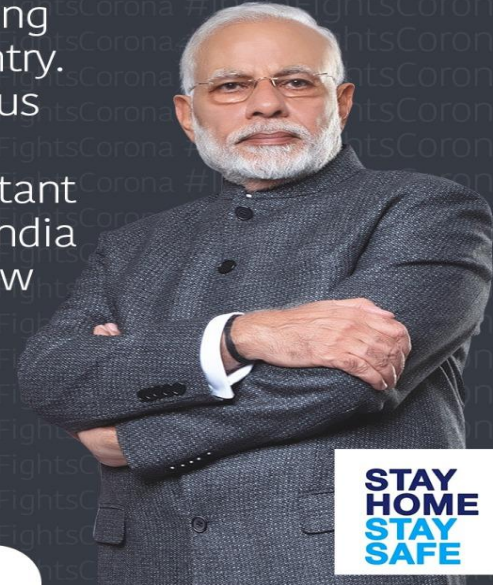
COVID-19 Daily Update



WORLD IS LOOKING UP TO INDIA TO FIGHT THE MENACE OF CORONA

"India led the world in eradicating two silent killers and eliminating them from the country. India has tremendous capacities. It is exceptionally important that countries like India lead the way to show the world what can be done."

Michael Ryan,
Executive Director, WHO



STAY HOME STAY SAFE

[f](#) [t](#) [v](#) [@](#) /BJP4India [www.bjp.org](#)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के लोगों से किए गए संवाद के मुख्य बिंदु

- आप जानते हैं, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप हैं। उन्हें प्रकृति की देवी भी कहा जाता है। आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, उसमें हम सभी को मां शैलसुते के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है।
- आपका सांसद होने के नाते मुझे, ऐसे समय में आपके बीच होना चाहिए था। लेकिन आप यहां दिल्ली में जो गतिविधियां हो रही हैं, उससे भी परिचित हैं। यहां की व्यस्तता के बावजूद मैं वाराणसी के बारे में निरंतर अपने साथियों से अपडेट ले रहा हूं।

- आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए. संकट की इस घड़ी में, काशी सबका मार्गदर्शन कर सकती है, सबके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है.
- काशी का अनुभव शाश्वत, सनातन, समयातीत है। और इसलिए, आज लॉकडाउन की परिस्थिति में काशी देश को सिखा सकती है- संयम, समन्वय, संवेदनशीलता. काशी देश को सिखा सकती है- सहयोग, शांति, सहनशीलता. काशी देश को सिखा सकती है- साधना, सेवा, समाधान.
- देखिए, मनुष्य का स्वभाव होता है कि जो कुछ भी सरल हो, खुद के अनुकूल हो, उसे जल्दी स्वीकार कर लेता है। कोई बात आपको अपने पसंद की लगती है, आपको सूट करती है तो आप उसे तुरंत सच मान लेते हैं. देखिए इस बीमारी में जो बातें सामने आई हैं, उसमें सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये बीमारी किसी में भेदभाव नहीं करती। ये समृद्ध देश पर भी कहर बरपाती है और गरीब के घर में भी कहर बरपाती है.
- नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए। हमें घर में रहना चाहिए और आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी से दूर रहने का अभी यही एकमात्र उपाय है.
- आप ये भी ध्यान रखिए कि कोरोना से संक्रमित दुनिया में 1 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से बाहर निकले हैं। कल तो एक खबर में देख रहा था कि इटली में 90 वर्ष से ज्यादा आयु की माताजी भी स्वस्थ हुई हैं.
- आपने देखा होगा कि 22 मार्च को किस तरह पूरे देश ने जनता कर्फ्यू में बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। और फिर शाम के ठीक 5 बजे, 5 मिनट के लिए कैसे देश भर के लोग अभिवादन के लिए सामने आए. समाज के मन में इन सब के लिए आदर सम्मान का भाव होता ही है। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। जिन लोगों ने वुहान में रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मैंने उनको पत्र लिखा था, मेरे लिए वो पल बहुत भावुक थे.

- हां कुछ स्थानों से ऐसी घटनाओं की जानकारी भी मिली है, जिससे हृदय को चोट पहुंची है। मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि कहीं दिख रही है। कहीं आपको डॉक्टर, नर्स या मेडिकल स्टाफ के साथ कोई बुरा बर्ताव होता दिख रहा हो तो आप वहां जाकर लोगों को समझाएं।
- संकट की इस घड़ी में, अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहा हर व्यक्ति, ईश्वर का ही रूप है। आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं। अपने जीवन को खतरों में डालकर ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं।
- कोरोना वायरस न हमारी संस्कृति को मिटा सकता है और न ही हमारे संस्कार मिटा सकता है। और इसलिए, संकट के समय, हमारी संवेदनाएं और जागृत हो जाती हैं। कोरोना को जवाब देने का एक तरीका करुणा भी है। यानि कोरोना को करुणा से जवाब. हमारे समाज में, हमारी परंपरा में तो दूसरों की मदद की एक समृद्ध परिपाटी रही है। साईं इतना दीजिए, जामें कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधू ना भूखा जाए !!
- अभी नवरात्र शुरू हुआ है। अगर हम अगले 21 दिन तक, 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें, तो इससे बड़ी आराधना मां की क्या होगी। इसके अलावा आपके आसपास जो पशु हैं, उनकी भी चिंता करनी है।
- जो तकलीफें आज हम उठा रहे हैं, जो मुश्किल आज हो रही है, उसकी उम्र फिलहाल 21 दिन ही है। लेकिन अगर कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ, इसका फैलना नहीं रुका तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।
- आप सोचिए, अस्पतालों में लोग 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। कई जगह अस्पतालो में, हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को 2-3 घंटे से ज्यादा सोने को नहीं मिल रहा। कितने ही सिविल सोसायटी के लोग हैं जो गरीबों की मदद के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं. निराशा फैलाने के लिए हजारों कारण हो सकते हैं लेकिन जीवन तो आशा और विश्वास से ही चलता है। नागरिक के नाते कानून और प्रशासन को जितना ज्यादा सहयोग करेंगे, उतने ही बेहतर नतीजे निकलेंगे.

- आपने खबरों में भी देखा होगा कि, दुनिया के कुछ देशों में अपनी मर्जी से दवाएं लेने के कारण कैसे जीवन संकट में पड़ रहे हैं। हम सभी को हर तरह के अंधविश्वास से, अफवाह से बचना है। हमें ये ध्यान रखना है कि अभी तक कोरोना के खिलाफ कोई भी दवाई, कोई भी वेक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बनी है। इस पर हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी काम तेज़ी से चल रहा है।

Relief Package announced by FM Nirmala Sitharaman under PM Gareeb Kalyan Yojna

- Under PM Gareeb Kalyan Yojna, Rs 1.7 lakh crores is sanctioned for the migrant workers and the poor who need immediate help. Govt will ensure no one goes hungry.
- 5 kgs of rice/wheat will be provided to 80 crore people free of cost for the next three months over what they're already getting. They will also receive 1 kg of pulses (depending on the region).
- 8.7 crore farmers to be immediately benefited through Direct cash transfers. Installment of Rs 2000 in the first week of April will be transferred.
- Rs. 1,000 extra will be given to the DIVYANG people as well. 3 crore such people will benefit from it. All of this will be transferred by DBT scheme.
- Women Jan-Dhan account holders will get Rs 500 every month for the next three months. This would benefit 20 crore women. This is being given to help them run their orders.
- For women benefitting from the Ujjwala Scheme, so that they don't run short of cooking medium in this period of disruption, for three months, they'll be given free cylinders. 8.3 crore BPL families will benefit from this.
- Through 63 lakh SHGs in the country, which benefit 7 crore households, under the National Rural Livelihood, they get up to Rs 10 lakh loans with collateral. Government of India is doubling that to Rs 20 lakhs. This applies immediately to all SHG women.

- Govt of India will pay the EPF contribution both of the employer and the employee, 24% in total (12%+21%), for the next 3 months, so that nobody suffers. This is for all those establishments which have up to a 100 employees and 90% of whom are earning less than Rs 15,000 per month.
- The PF scheme regulations will be amended because of the pandemic situation to allow the non-refundable advance of 75% of the amount standing credit to the user or 3 months wages, whichever is lower. This will benefit 4.8 crore workers.
- At present, Rs 31,000 crore is available in the Building and other Construction Workers' Fund (BOCW). These can be used for 3.5 crore construction workers. The Govt has suggested State Govts to utilize this for the welfare of these workers.
- Wage increase in MGNREGA- 5 crore families to benefit with an increase of Rs 2000 per worker on average as additional income.
- For 3 crore people - Old age, Divyang & pensioners, one-time amount of additional Rs 1000 in two installments through DBT over 3 months to be given.

Insurance scheme for health workers fighting COVID-19 in Government Hospitals and Health Care Centres :

- Safai Karamcharis, ward-boys, nurses, paramedics, technicians, doctors and specialists and other health would be covered by a Special insurance Scheme.
- Any health professional who while treating Covid-19 patients or meets with some accident, then he/she would be compensated with an amount of Rs 50 lakh under the scheme.
- All government health centres, wellness centres and hospitals of Centre as well as States would be covered under this scheme approximately 22

lakh health workers would be provided insurance cover to fight this pandemic.

India Fights Corona (Updates)

- स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल : देश में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 629 हैं। इसके साथ ही 13 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 43 नए केस आए हैं और 4 नई डेथ रिपोर्ट हुई है।
- COVID19 के मद्देनजर भारत सरकार ने लोगों को दवाओं की डिलीवरी घर तक पहुंचने की अनुमति दी। अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संयुक्त सचिव, लव अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के अनुरोध पर COVID19 समर्पित अस्पतालों के लिए लगभग 17 राज्यों में काम शुरू हो गया है।
- ओडिशा देश का सबसे बड़ा COVID19 अस्पताल स्थापित करने जा रहा है, इसमें 1000 बेड होंगे। ओडिशा देश का पहला राज्य होगा जो #COVID19 रोगियों के इलाज के लिए इतना बड़ा अस्पताल स्थापित करेगा।
- सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की तारीफ करते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा कि यह कदम इतने प्रभावी हैं कि अगर हम उनका सख्ती से पालन करें तो देश में कोरोना वायरस के मामले मुश्किल से बढ़ेंगे.
- महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 125 हो गई है।

- स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार: राज्य में कोरोना वायरस के कुल मामले अब 18 हो गए हैं। फरीदाबाद में 2, गुरुग्राम में 10, पलवल में 1, पानीपत में 3, पंचकुला में 1 और सोनीपत में 1 मामला सामने आया है।
- तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग: राज्य में कोरोना वायरस से ग्रस्त मामलों की कुल संख्या 43 हो गई है, कोरोना वायरस के लिए 3 और व्यक्तियों के टेस्ट के नतीजे पॉजिटिव आए हैं। अभी तक राज्य में एक व्यक्ति ठीक हो चुका है, उसे छुट्टी दे दी गई है।
- राजस्थान: जयपुर में एक 45 वर्षीय व्यक्ति और झुंझुनू के एक 35 वर्षीय व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। दोनों की विदेश यात्रा से लौटे थे। उनके संपर्क की ट्रेसिंग चल रही है। राज्य में कुल कोरोना मामलों की संख्या 40 हो गई है।
- चेतन सांघी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक व्यक्ति का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसने 24 मार्च को चेन्नई से उड़ान भरी थी। प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
- असम, गुवाहाटी: कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम (Sarusajai) में कोरोना वायरस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है।
- ई-रिटेलर्स को आवश्यक सेवाएं और सामान वितरित करने की अनुमति दी गई है। सभी आवश्यक सेवाओं की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी ताकि लोगों की भीड़ कम हो: दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रधान सचिव डॉ. जयंती रवि: गुजरात कोरोना वायरस की जो भी लेटेस्ट सूचना है वो आपको गुजरात

डैशबोर्ड से मिलती रहेगी। <http://gujccovid19.gujarat.gov.in> पर दिन के दो मरतबा डाटा को अपलोड किया जाएगा और इसमें धीरे-धीरे और भी डाटा डाला जाएगा।



Updates from WHO on Corona Virus

Media Briefing from Tedros Adhanom Ghebreyesus, DG, WHO

- "We have overcome many pandemics and crises before. We will overcome this one too. The question is how large a price we will pay". "Already we have lost more than 16,000 lives. We know we will lose more – how many more will be determined by the decisions we make and the actions we take".
- To slow the spread of COVID19, many countries introduced "lockdown" measures. But on their own, these measures will not extinguish epidemics. We call on all countries to use this time to attack the coronavirus. You've created a 2nd window of opportunity.
- "The point of these actions is to enable the more precise and targeted measures that are needed to stop transmission and save lives. We call on all countries who have introduced so-called "lockdown" measures to use this time to attack the #coronavirus".
- "You have created a 2nd window of opportunity. How will you use it?"

- Expand, train & deploy your health care & public health workforce
 - Implement a system to find every suspected case at community level
 - Ramp up the production, capacity & availability of testing"
 - Identify, adapt and equip facilities you will use to treat & isolate patients
 - Develop a clear plan & process to quarantine contacts
 - Refocus the whole of government on suppressing & controlling
- "These measures are the best way to suppress & stop transmission, so that when restrictions are lifted, the #coronavirus doesn't resurge. The last thing any country needs is to open schools & businesses, only to be forced to close them again because of a resurgence"
 - "Aggressive measures to find, isolate, test, treat and trace are not only the best and fastest way out of extreme social and economic restrictions – they're also the best way to prevent them"
 - "More than 150 countries & territories still have fewer than 100 cases. By taking the same aggressive actions now, these countries have the chance to prevent community transmission & avoid some of the more severe social & economic costs seen in other countries".
 - "This is especially relevant for many vulnerable countries whose health systems may collapse under the weight of the numbers of patients we've seen in some countries with community transmission"
 - "Physical distance doesn't mean social distance. We all need to check in regularly on older parents, neighbors, friends or relatives who live alone or in care homes in whatever way is possible, so they know how much they are loved and valued".

भाजपा सरकारों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदम

उत्तर प्रदेश

- प्रदेश में 12 हजार से अधिक वाहन सब्जी, दूध, दवा एवं खाद्यान्न घर-घर पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक भोजनालय के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। रैन बसेरों, बस एवं रेलवे स्टेशनों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी व्यक्ति भूखा-प्यासा नहीं रहे यह प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग अपने-अपने घरों में रहें और इस वैश्विक महामारी से लड़ने में अपना सहयोग दें।
- प्रदेश में 2000 आइसोलेशन बेड थे, जो विभिन्न जनपदों के वार्डों में मौजूद थे। पिछले 2-3 दिनों में इन बेडों की संख्या 10,000 तक किया गया है।
- प्रदेश में श्रम विभाग के अंतर्गत 20.37 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें 5.97 लाख श्रमिकों के बैंक खातों का डेटा विभाग के पास उपलब्ध है। ऐसे श्रमिकों के खातों में प्रतिमाह ₹1,000 की धनराशि भेजे जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। जिन श्रमिकों के खाते नहीं हैं, उनके खाते जल्द से जल्द खुलवाकर विभाग में 'Labour Cess Fund' से सभी 20.37 लाख श्रमिकों को ₹1000 प्रतिमाह डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके एकाउंट में भेजे जाएंगे।
- प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 1.65 करोड़ जरूरतमंदों को एक माह निःशुल्क राशन, माह अप्रैल में उपलब्ध कराया जाएगा। जो परिवार किसी सरकारी योजना से आच्छादित नहीं है, यदि उनके भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं है, तो समुचित प्रावधानों के तहत उन्हें भी ₹1000 प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

- प्रदेश सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को दो माह की अग्रिम पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह राशि अप्रैल माह में दी जाएगी। मनरेगा के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्य के संदर्भ में लगभग ₹556 करोड़ की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही मार्च, 2020 में ही कराई जाएगी।

उत्तराखंड

- लॉक डाउन की स्थिति में मजदूर छोटे कारीगर प्रभावित न हों, इसके लिए सरकार ने राज्य में रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में एक हजार रुपए डालने का फैसला किया है, ताकि उनको खाद्यान्न की दिक्कत न हो।
- किसी भी प्रकार की खाद्यान्न व औषधियों की कमी जनता को न हो, इसलिए प्रदेश सरकार घर-घर जाकर खाद्यान्न व दवाइयां पहुंचाएगी।

Karnataka

- State assured that during 'Lockdown', all essentials like food, vegetable and fruit shops, pharmacies, ATMs, petrol bunks, etc, will remain open.
- A 24/7 war room has been set up in the Balabrooie guest house to effectively combat the Covid19 menace in the State. Chief Minister will be personally monitoring the war room to activities to ensure quick action against any kind of emergency.
- Ensuring that there is no dearth of beds for the treatment of Covid_19, Chief Minister has announced that 1700 beds will be dedicated for the treatment in Victoria Hospital.

Tripura

- Distribution of 15 Days' Rice at free of cost for AAY and PHH Ration Card holders to ensure relief to the poorer section of the State during the Lock down imposed to contain the spread of COVID19.
- Tripura Government will be distributing cooked food items among the homeless people during the 21 days Lockdown throughout the State. Food packets will be served two times every day.

Assam

- A large quarantine centre will be established at the Sarusojai Sports Complex, Guwahati with capacity for about 700 people.
- To ensure strict adherence to practice of Social Distance, Assam Govt. have introduced stamping at Guwahati airport for those coming from outside, for home quarantine.

सरकार ने सुरक्षित, घर पर रहने का इंतजाम किया

हर्ष वर्धन त्रिपाठी

22 मार्च 2020, रविवार को विश्व इतिहास में एक ऐसी तारीख के तौर पर याद किया जाएगा, जिस दिन दुनिया ने भारतीयों की सामूहिक शक्ति का नाद सुना। पूरा हिन्दुस्तान ताली, थाली और शंखनाद के लिए एक साथ शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए इकट्ठा हो गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि कुछ मानसिक विकृति के शिकार लोगों को छोड़कर मोदी विरोध करने वाले भी ताली, थाली और शंख बजाते अपने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर रहे थे। यह देश के एक साथ खड़े हो जाने का 5 मिनट था जो 5 बजे से पहले शुरू हो गया था और 5 बजकर 5 मिनट से भी बहुत देर तक चलता रहा। यह वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसमें साथ खड़े होकर भी हर कोई आगे रहने की कोशिश कर रहा था। यह सामान्य बात नहीं है। दरअसल, देश को इस तरह से एकजुट होने की जरूरत बहुत लम्बे समय से थी। 2010 में जब देश के शीर्ष 10 उद्योगपतियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर सरकारी नीतियों में भरोसा न

होने की बात लिखी थी, तभी से देश को एकजुट करने वाले एक मजबूत नेता की जरूरत थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने यह करके दिखा दिया था और उसी का नतीजा है कि 2014 और फिर 2019 में जनता ने प्रचण्ड बहुमत से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है। इस समय देश चीनी वायरस कोरोना की अकल्पनीय चुनौती से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतर्कतापूर्वक एक-एक कदम आगे बढ़ाते हुए जनता कर्फ्यू के बाद अब 21 दिन की देशबंदी का एलान कर दिया है। ज्यादातर लोग इसे सही मानते हैं क्योंकि दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, लेकिन सबके मन में एक जायज चिंता थी कि आखिर क्या होगा हिन्दुस्तान की उस बड़ी आबादी का, जिसके लिए 21 दिन में भुखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसी आपदा, महामारी का सबसे बुरा प्रभाव सबसे कमजोर लोगों पर ही पड़ता है। इसीलिए सरकार से उम्मीद का जा रही थी कि ऐसे लोगों को राहत देने वाला पक्का आर्थिक पैकेज जल्द से जल्द लेकर आए। आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार उस भरोसे पर खरी उतरी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में खास ध्यान किसान, प्रवासी मजदूर, शहरी और ग्रामीण गरीब, महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगों का रखा गया है। किसानों की खेत में खड़ी फसल पकने का यह समय है और करीब 15 दिन में फसल काटने का वक्त आ जाएगा। किसानों को अभी तुरन्त पैसों की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 करोड़ 90 लाख किसानों को राहत देने वाला एलान किया है। केंद्र सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल महीने में देगी। इसमें एक और जरूरी काम जो राज्य सरकारों को करना चाहिए कि खेत में खड़ी फसल कटने का पक्का इंतजाम पहले से करें, जिससे किसानों को फसल काटने और उसे बेचने में किसी तरह की दिक्कत न हो। डॉक्टर

पृथ्वी पर भगवान का रूप होता है, इस समय हर किसी को समझ में आ रहा है। डॉक्टरों के साथ ही नर्स, आशाकर्मी और सभी स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता सबसे जरूरी है। इसी चिंता को ध्यान में रखने हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़े कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया है। इस समय कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर नहीं मिल पाने का खतरा भी बढ़ जाता है और साथ ही कंपनियों के लिए बंदी के समय कर्मचारियों की तनख्वाह और उनके EPF का 12 प्रतिशत हिस्सा जमा करना चुनौती होती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने आज कर्मचारियों और छोटी कंपनियों को राहत दी है। जिन कर्मचारियों का एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड कटता है, ऐसे कर्मचारी EPF से नॉन रिफंडेबल 75 प्रतिशत तक रकम निकाल सकेंगे। EPF रकम में से 3 महीने की तनख्वाह के बराबर या फिर EPF की 75 प्रतिशत तक की रकम जो भी कम हो, निकाल सकेंगे। इससे 4 करोड़ 80 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी। साथ ही केंद्र सरकार छोटे उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की EPF की पूरी रकम अगले 3 महीने तक भरेगी। हालांकि यह राहत अधिकतम 100 कर्मचारियों वाले और उनमें से 90 कर्मचारियों की तनख्वाह 15 हजार रुपये महीने से कम वाले उद्योगों के लिए ही है।

देशबंदी के समय सारे काम ठप पड़ जाते हैं और काफी बुरा प्रभाव कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर पड़ता है। देश में कुल 3 करोड़ 50 लाख पंजीकृत बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। राज्यों को सेस फंड में इकट्ठा 31 हजार करोड़ रुपये की रकम इन निर्माण क्षेत्र के मजदूरों की भलाई के लिए खर्च करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और दूसरी राज्य सरकारें सीधे ऐसे मजदूरों के खाते में रकम डाल रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग करने की स्वीकृति दी है। इस फंड से स्वास्थ्य सुविधाएं और टेस्टिंग की सुविधा बेहतर करने में किया जाएगा। नोटबंदी, जनधन और डीबीटी की खूब जमकर आलोचना हुई थी और जब

नरेंद्र मोदी सरकार ने इन सुधारों को लागू किया था तो आलोचक यही कहने लगे थे कि डिजिटल बैंकिंग के अलावा क्या मिला। आज इस सवाल का जवाब पूरी मजबूती से मिल रहा है। सरकार आज नोटबंदी, जनधन और डीबीटी की ही वजह से सीधे जरूरतमंदों के खाते में रकम डाल पा रही है। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में अगले 3 महीने तक 500 रुपये प्रतिमाह सरकार डालेगी। इसी तरह देश में करीब 3 करोड़ बुजुर्ग, दिव्यांग पेंशनधारक हैं, इन्हें अगले 3 महीने में 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। उज्ज्वला से देश के गरीब और महिलाओं को कितना लाभ हुआ है, इस पर अब ढेरों शोध पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन इसकी एक आलोचना यह भी हो रही थी कि लोगों के पास रसोई गैस सिलिंडर दोबारा भराने के पैसे नहीं हैं। अब उज्ज्वला के तहत रसोई गैस सिलिंडर और चूल्हे मुफ्त में पाने वाले सभी 8 करोड़ 30 लाख लोगों को अगले 3 महीने तक मुफ्त में सिलिंडर दिया जाएगा। समाज के सबसे कमजोर के साथ आपदा की घड़ी में साथ खड़े रहने में सरकार की मदद वही फैसले कर रहे हैं, जिसे सरकार ने शांतिकाल में लिया था। उसमें नोटबंदी, जनधन खाते, डीबीटी, उज्ज्वला जैसी योजनाएं हैं। केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने का भी खूब प्रयास किया। अब ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाया है, उनके पास ऐसे समय में रकम रहे, इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत दिया जाने वाला कर्ज दोगुना कर दिया गया है। अब बिना गिरवी रखे 20 लाख तक का कर्ज उन्हें मिल सकेगा। ऐसे स्वयं सहायता समूहों से करीब 7 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं। सरकार को इस बात का ध्यान बखूबी है कि सबसे ज्यादा मार ऐसे समय में सबसे कमजोर लोगों पर पड़ती है। इसीलिए सरकार ने ऐसे लोगों को अलग-अलग तरीके से राहत देने के साथ उनके हाथ में कुछ रकम और सिलिंडर तक का पक्का इंतजाम अगले तीन महीने के लिए कर दिया है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हर किसी के पास दोनों समय के भोजन का पक्का इंतजाम हो और इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80

करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और एक किलो दाल भी दी जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आज जिस एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया है, अच्छी बात यही है कि उसके लिए बजट का प्रावधान सरकार ने पहले से कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का जो भरोसा है, उसका प्रयोग उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में रकम देने के लिए करना चाहिए। केंद्र सरकार को एक बेहद जरूरी काम तुरन्त एलान करना चाहिए कि सामान्य कर्ज से लेकर उद्योगों तक का कर्ज पर अगले कम से कम तीन महीने के लिए ईएमआई हॉलीडे दिया जाएगा। सामान्य लोगों और छोटे-मंझोले उद्योगों को राहत देने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है, जिसका देश इंतजार कर रहा है। देश के लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनौतियों को अवसर में बदलना अच्छे से जानते हैं और देश के सामने आई इस सबसे बड़ी चुनौती को भी वो सबसे बड़े अवसर में बदल देंगे, इसलिए देश की जनता प्रधानमंत्री के हर फैसले के साथ अडिग खड़ी है और केंद्र सरकार का ताजा आर्थिक पैकेज देश की जनता, खासकर कमजोर वर्ग को ज्यादा भरोसा देगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो हैं। लेख में व्यक्त उनके विचार निजी हैं।)

India Fights Corona



MyGovIndia ✓

@mygovindia



The Sarpanch of Deoria Gram Panchayat, Bhilwara, [@SarpanchOnline](#), is a true [#CoronaWarrior](#).
[#IndiaAgainstCorona](#)



सरपंच Kismat @SarpanchOnline · 1d

साथ ही #COVID19 के संक्रमण से बचाव के उपायों हेतु जनजागृति हेतु जन जन को पेंपलेट और हाँथों में पहनने के दस्ताने तथा मास्क वितरित किए।

[Show this thread](#)



12:04 · 26 Mar 20 · [Twitter Web App](#)

Help us to
help you

my
Gov
मेरी सरकार

Stay Home, Save Lives.



#IndiaFightsCorona